इम्तिहानों में उलझता भारतीय युवा

ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

भाजपा सरकारें रोजगार का झाँसा देकर बेरोजगारों की जेब काटने में लगी हुयी हैं। बीते 5 अगस्त को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए पहले चरण का इम्तिहान हुआ। इसमें पाँच लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने 350 रुपये प्रति फॉर्म भर कर शिरकत की। प्रशासन का दावा है कि इस बार लगभग एक लाख पचास हजार के करीब ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। ये छोटा सा आंकड़ा अपने आप में काफी है कि रोजगार का असली आयाम क्या है भाजपा राज में।

यही नहीं, अभ्यर्थियों की गत और तरह भी बनती है। गत कई माह से करीब हर राज्य में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशासन बिना नकल परीक्षा कराने के नाम पर एक से बढ़कर एक बेवकूफी भरे प्रयोग कर रहा है। राजस्थान परीक्षा में अभ्यर्थियों को चप्पल, हाफ शर्ट, और पारदर्शी पेन के साथ दो घंटे पूर्व परीक्षा सेंटर पर आने का निर्देश दिया गया।

सिपॉय रोड, धौलपुर पर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज के सेंटर पर अभ्यर्थियों का जमावड़ा 8 बजे से ही लगना शुरू हो गया पर प्रवेश 9.30 पर ही शुरू हुआ। भीलवाड़ा के रहने वाले 37 वर्षीय हरीश बैंक आफ बड़ोदा में कार्यरत हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए ये उनका पांचवा प्रयास है और पहली बार पाया कि सेंटर पर आये बच्चों को अपनी शर्ट की बाजू तक काटनी पड़ गई। लड़कियों के मंगलसूत्र और यहाँ तक कि सभी अभ्यर्थियों की चप्पले तक उतरवा दी गई। शौच इत्यादि तक जाने के लिए नंगे पैर ही जाना पड़ा।

दूर दराज से आये अभ्यर्थियों के झोले एवं दूसरे सामान रखने की सुविधा देने के एवज में कालेज प्रसाशन ने सभी बच्चों से 10 रुपये वसूलने शुरू कर दिए। इस लूट में बैग जमा करने वाले व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 10 रूपए और जोड़ दिए और इस प्रकार सभी से 20 रूपए बैग के वसूले जाने लगे।

इसी प्रकार पीएमटी की परीक्षा के दौरान केरल और हरियाणा में लड़कियों के सूट के बाजू भी काटे गए। बाद में मालूम पड़ा कि रोहतक से परचा लीक हो चुका है। हिसार के कुछ सेंटरों पर अभ्यर्थी इस नकल रोको सख्ती से नाराज भी हुए और इसे

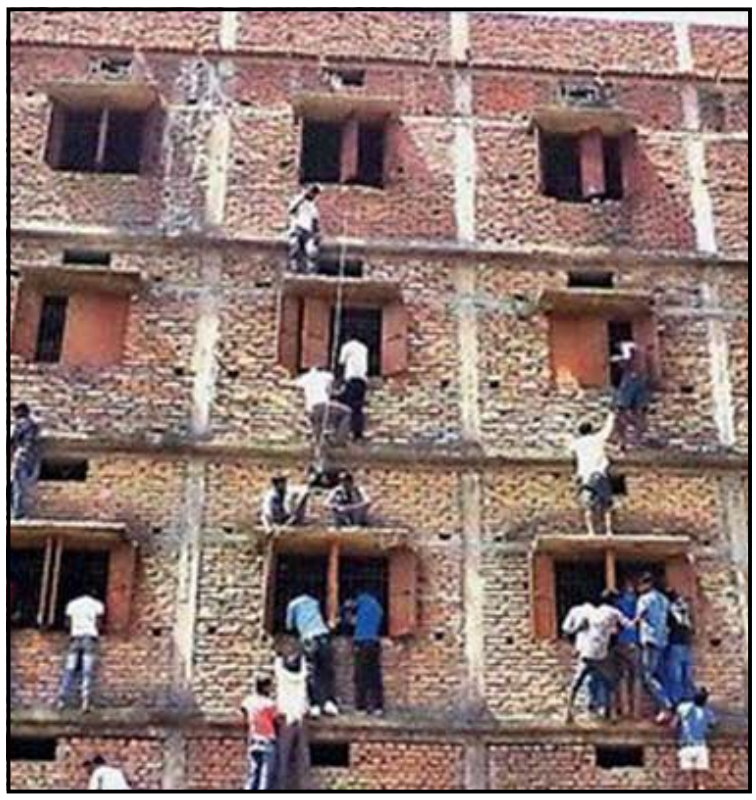

सरकार का उनके स्वाभिमान को ठेस पहुचाने वाला कदम बताया।

प्रथम दृष्टा प्रशासन का ये कदम राज्य ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया जान पड़ता है, वहीँ बच्चों का विरोध कम तर्कसंगत नहीं। 25 वर्षीय वैशाली दिल्ली की रहने वाली है और पहली बार पीसीएस का इम्तिहान देने धौलपुर पहूँची है। उनको अपनी कमीज की बाजू काटने में समस्या नहीं पर क्या सरकार इस तरह बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुँचा कर भी दोषरहित परीक्षा पूर्ण करा लेगी? ये संशय का विषय है।

एम्स दिल्ली में निविदा प्रक्रिया से लैब सहायक के पद पर कार्यरत 22 वर्षीय फहरीन अंसारी ने बताया कि पीसीएस का इम्तिहान देना उनकी मजबूरी है क्योंकि एम्स में पिछले दो बार से सहायक की पोस्ट को पक्का करने के लिए इम्तिहान लिया गया और रिजल्ट नहीं निकाला गया। अब नौकरी की असुरक्षा ने दूसरे अवसरों को तलाशने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ आ कर मालूम पड़ा कि राज्य आयोगों के हाल इससे भी बुरे हैं।

जुलाई माह में हुई रेलवे की भर्ती में बिहार के परीक्षार्थियों को हैदराबाद, केरल वालों को पानीपत और गुजरात वालों को बिहार के सेंटर देने जैसे सैकड़ों मामले सामने आये। जाहिर है इतनी दूर जाना अपने आपमें खर्चीला है और उसपर भारतीय रेल का समय पर न पहुँचने का वादा भी पक्का होता है।

उत्तर प्रदेश के मऊभंजन नाथ जिले के रहने वाले अनित चौधरी को सेंटर मिला तेलंगाना में। घर से दो दिन पहले निकलने पर भी आदतानुसार ट्रेन इतनी लेट हुई कि 15 मिनट की देरी से वे अपने सेंटर पहुचे। इस 15 मिनट की देरी की माफी नहीं मिली क्योंकि अब प्रशासन वक्त का पाबन्द हो गया। इसी कारण इम्तिहान से चूक गए और वक्त के साथ पैसे की भी बर्बादी बर्दाश्त करनी पड़ी।

प्रश्न ये है कि इतनी परेशानियाँ और किल्लत उठाने के बाद इन लाखों लाख अभ्यर्थियों को अंत में मिलता क्या है? जवाब है सिर्फ इंतजार। बच्चों से पहले पहुँचने और सुरक्षा शर्तों पर खरा उतरने की शपथ लेने वाली सरकारें खुद ही इन सब मापदंडों को ताक पर रखती हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं।

सीबीएससी के परचा लीक होने की घटना अभी हाल ही में घटी है। इसी तरह पीएमटी के इम्तिहान में इतने एहतिआत का ढोंग करने वाली भारत सरकार बाकियों की चप्पलें और कमीजें उतरवाती रही और दूसरी तरफ परचा लीक हो गया। खुद की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की बजाय सरकारें सिर्फ ढोंग में शामिल हैं, एक से बढ़कर एक सभी।

उत्तर प्रदेश पीसीएस की पिछले साल होने वाली मुख्य परीक्षा होते होते 2018 में हुई और अभी उसका परिणाम आना बाकी जबकि इस वर्ष होने वाली परीक्षा की तारीख बदल कर 28 अक्टूबर तक खिसका दी है।

हरियाणा नायब तहसीलदार का इम्तिहान पिछले तीन वर्ष से नहीं हो सका है जबकि फार्म हर साल भरवा कर सरकार 500 रूपए वसूल लेती है और इस बार फिर ये फार्म निकाला गया। इसी प्रकार हरियाणा पीएससी की पिछले वर्ष की परीक्षा इस साल 4 साल बाद आयोजित की जा रही है जिसकी फीस 1000 रूपए तक है। परीक्षा कब होगी इसका कोई अंदाजा नहीं।

सबको रोजगार, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जुमला उड़ाने वाले मोदी एंड कम्पनी न अपने आयोगों को सुधार सकी है न ही कोई परीक्षा सफल रूप से करा सकी है। पार्टी के नक्शेकदम पर चलते हुए अब हरियाणा सरकार की शहरी विकास मंत्री कविता जैन ने 50000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा गुरुग्राम में की, साथ ही सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत 45422 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है का झूठ भी बता दिया। जबकि वहीँ प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े हो कर रोजगार का आंकड़ा ऑटो खरीदने और डिग्री मिलने से जोड़ कर बताया।

जब देश का प्रधानमंत्री ही संसद और लाल किले के प्राचीर से झूठे आंकड़ें और झूठा प्रचार करता हो तो इन आयोगों और छुटपुट मंत्रियों से सच और रोजगार केन्द्रित योजनाओं की उम्मीद बेमानी है।

लगभग सभी राज्य सरकारें न समय से रिजल्ट की घोषणा करती हैं न भर्ती, बस फॉर्म शुल्क से अपना राजस्वा बढाती हैं। जबकि संघ लोक सेवा आयोग का सफल माँडल सबके सामने मौजूद है जहाँ हमेशा सफल और समय पर प्रक्रिया पूरी होती आई है। इसलिए सालों से इम्तिहानो की चैन में उलझे युवाओं ने अब अपने दिल की तसल्ली को नए वाक्य गढ़ लिए हैं।

पहले इम्तिहान तीन चरण में होते थे प्री, मैन्स, और इंटरव्यू, पर अब इसके कई चरण हैं जिसमे इंटरव्यू के बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर रीएग्जाम भी शामिल हो गए हैं पर रिजल्ट आने की संभावना नगण्य ही रहेगी।

सुरसा का मुंह बन गया है बेरोजगार

इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन की हाल में रोजगार पर प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल और बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 1 करोड़ 83 लाख लोग बेरोजगार थे जबकि इस साल इसमें 3 लाख लोग बढ़ गए हैं।

श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार लोगों का देश बन चुका है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लगभग 11 प्रतिशत आबादी। मोदी जी स्वरोजगार की डींगें हाँकते नहीं थकते जबकि रिपोर्ट कहती है कि देश में स्वरोजगार के अवसर कम हुए हैं। वही यूएनएलओ की रिपोर्ट ने बताया कि 2018 में भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी जो अब दिखाई भी दे रही है।

इसका जिम्मा भारत सरकार और मोदी ब्रिगेड के नेताओं का है जो सत्ता के नशे में सभी युवाओं को अपना पार्टी कार्यकर्ता या काँवडिया बनाने पे तुले हैं। सभी राज्य युवाओं को न रोजगार दे पा रहे हैं न उनकी नीयत है। साथ ही जो युवा निजी संस्थानों में कार्यरत हैं उनकी रोजगार की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करने की जहमत सरकार नहीं उठा रही। किसी भी कर्मचारी को उसकी नौकरी से निष्कासित कर देना निजी संस्थानों या व्यक्तियों का रोज का काम है। जबकि सरकार लेबर कानूनों का पालन नहीं करा पा रही इन निजी सेक्टर के पूंजिपतियों से।

अच्छे दिन लाने का दावा करने वाले जुमला मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आपके राज में आम नागरिक के धक्के कितने कम हुए? रोजगार तो दूर आप अपनी निकाली सीटों की परीक्षा तक पूरी नहीं करा पाते सालों साल। इसलिए अब आप जाने वाले हैं।

आधुनिक बस अड्डा जरूर बनायेंगे, बसें नहीं चलायेंगे

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले का सबसे बड़ा बस अड्डा बल्लबगढ में करीब 35 साल से बना खड़ा है। किसी जमाने में यहां से सैंकड़ों बसें नियमित रूप से निकलती थीं, हज़ारों यात्री इसका लाभ उठाते थे। बसों की देख-भाल एवं रख-रखाव के लिये अच्छी-खासी वर्कशॉप भी यहां चलती थी जिसमें कुशल कामगार रात-दिन काम करके बसों को सुचारु रूप से चलाये रखते थे। आज यह बस अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वर्कशॉप में कव्वे बोल रहे हैं। बसें खटारा बनी खड़ी हैं; जो चालू हैं भी उन्हें चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर नहीं। लिहाज़ा सवारियां वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं।

जनविरोधी खट्टर सरकार परिवहन व्यवस्था को सुधारने की अपेक्षा करोड़ों रुपया बर्बाद करके एनआईटी में एक नया आधुनिक बस अड्डा बनाने की तैयारी में है। इस अड्डे से किसी यात्री को यात्रा करने के लिये बस मिले या न मिले परन्तु यहां शॉपिंग करने की पूरी सुविधा मिलेगी। मौज मस्ती के लिये उत्तम श्रेणी के रेस्त्रां खोले जायेंगे। यानी एक तरह की मॉल संस्कृति को बढावा दिया जायेगा। जाहिर है बस अड्डे एवं यात्रियों की सुविधा के नाम पर खट्टर सरकार यहां एक व्यापारिक केन्द्र खड़ा करेगी। इसमें, पहले तो निर्माण के समय मोटी लूट कमाई का सिलसिला चलेगा और बाद में व्यापारिक स्थलों को बेचने अथवा लीज़ पर देने में धांधलेबाज़ी की जायेगी।

वास्तव में यात्रियों की जरूरत पर्याप्त मात्रा में बसों की है जो निश्चित समय सारिणी के अनुसार यात्रियों को सुखद सेवा दे सके। इसके लिये मौजूदा बस अड्डा पर्याप्त है। जरूरत है तो बसों की संख्या व आवश्यक स्टाफ़ को बढाने की। सुन्दर, आकर्षक व आधुनिक बस अड्डे में प्रवेश करने मात्र से तो किसी यात्री की यात्रा पूरी होने वाली नहीं। बस अड्डे पर आने वाला कोई भी यात्री अड्डे पर सैर करने या मौजमस्ती करने तो आता नहीं। उसे तो गंतव्य पर पहुंचाने वाली बस मिल जाये तो वह तुरंत उसमें सवार होकर निकलना चाहेगा। कोई भी यात्री अपना कीमती समय लेट-लतीफ़ बसों की इन्तजार में बर्बाद नहीं करना चाहता।

लेकिन जनविरोधी सरकार को इससे क्या लेना-देना, उसे तो जनहित के नाम पर तरह-तरह के ड्रामे व पाखंड करने से ही फुर्सत नहीं ।

बीस साल बाद बदल दी एफ.सी.आई में मजदूरों की डेट ऑफ बर्थ, चार साल बाद भी नहीं मिल पाया श्रमिकों को न्याय, अब यह मामला है केन्द्रीय औद्योगिक प्राधिकरण में कि क्या कोई व्यक्ति दो बार जन्म ले सकता है?

करनाल : (प्रवीण कुमार) क्या कोई व्यक्ति चार साल की उम्र में नौकरी पर लग सकता है। क्या किसी के सर्विस रिकार्ड में दर्ज उम्र को 20 साल बाद परिवर्तित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष तथा मौजूदा विदेश राज्यमंत्री वी.के सिंह के मामले में भी माना कि उम्र किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। इसे बदला नहीं जा सकता। भारतीय कानून के अनुसार सर्विस रिकार्ड में दर्ज उम्र तीन माह के भीतर तो बदली जा सकती है। उसके बाद नहीं बदल सकती। लेकिन एफ.सी.आई ने यह कारनामा कर दिखाया।

अफसरों ने लगभग 8 मजदूरों की आयु 20 साल बाद बदल दी और उन्हें रिटायर्ड कर दिया। मजदूर न्याय की लड़ाई लगातार लड़ रहे है। यह लड़ाई सी.एम सिटी में 3 साल से जारी है। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। पहले यह मामला श्रम विभाग के पास था। बाद में इसे सी.आई.टी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में ट्रांसफर कर दिया। अभी भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एफ.सी.आई में इस गड़बड़ी की कहानी 1985 से शुरू होती है। 29 नवम्बर 1985 एक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदेश के 22 डिपो जिनमें करनाल भी शामिल था, यहां पर ठेके पर काम करने वाली लेबर को एफ.सी.आई ने मजदूर बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद 4 जून, 1991 में एफ.सी.आई और श्रमिक यूनियन के बीच समझौता हुआ। जिसमें तय किया गया कि श्रमिकों की आयु सी.एम.ओ द्वारा तय की जाएगी। उसका प्रमाण पत्र अंतिम साक्ष्य होगा। उसके बाद 1991-92 में चोपड़ा कमेटी बनाई गई। इसको ठेकेदारी में लगे श्रमिकों को एफ.सी.आई का कर्मचारी बनाना था। 1994 में एस.आर.एम रंगा ने 251 मजदूरों की सूची बनाई। जिसके बाद एफ.सी.आई में इन मजदूरों को विभागीय श्रमिक के रूप में नियुक्त कर दिया गया।

28 अप्रैल 1994 में पीटिशन के बाद उनके आवेदन मांगे गए। 3 मई को सिनियरोटि के आधार पर सूची बनाई गई। बायोडाटा दिए गए। 1 अप्रैल, 1994 को सभी के सी.एम.ओ के द्वारा मैडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर जमा करवाए गए। श्रमिकों का मैडिकल बोर्ड ने परीक्षण किया। उनकी ज्वाईनिंग हुई। उस समय यह लिखा गया कि ये श्रमिक 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे।

उसके बाद एफ.सी.आई मजदूरों को जबरन रिटायर्ड करने के लिए 38 मजदूरों की सूची बनाई गई। यहां पर 8 मजदूरों को रिटायर्ड कर दिया गया। यह मामला लेबर कमिश्रर के यहां गया। लेबर कमिश्रर ने भी सवाल किया कि किस आधार पर आयु बदली गई। बताया जाता है कि यह मामला श्रमिक पिछले तीन साल से उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जंग बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि मामला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री के संज्ञान में लाया जा चुका है। लेकिन श्रमिकों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब यह मामला सी.आई.टी में चल रहा है।